

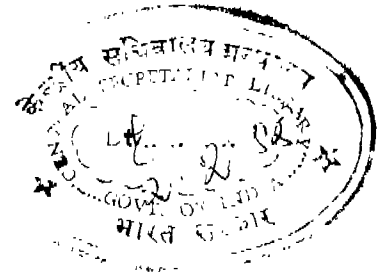


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 214]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 1987/अश्विन 23, 1909

No. 214]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1987/ASVINA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1987

निर्वात व्यापार निर्यात

सार्वजनिक धूना सं. 28 ई-टी (पीएन)/87

विषय:—1 जनवरी, 1988 से 31 दिसम्बर, 1990 तक संयुक्त राज्य
अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्ट्रेलिया,
फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को खुले सामान्य खाइसेंस
के अन्तर्गत योगाओं और सलाई से तैयार किए गए वस्त्रों को
निर्यात करने के लिए स्कीम।

फा. सं. 2/95/87-ई-1:—यह स्कीम तैयार योगाओं और सलाई
से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय
आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रांस, इटली,
बेनेलक्स, यू के, आयरिश), गणतंत्र, डेनमार्क, ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन)
आस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को 1 जनवरी, 1988
से 31 दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के लिए निर्यात से संबंधित है।

2. योजना को प्रणालित करने के लिए अधिकरण

जब तक अन्यथा रूप से निर्देश न दिया जाए तब तक परिधान निर्यात
संवर्धन परिषद् (ए.ई.पी.सी.) नई दिल्ली-निर्यात हकदारियों का आर्थिक
करेगी और इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी पायागों और सलाई
से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी, परन्तु सलाई से
बुने हुए ऊनी वस्त्रों की हकदारी का आर्थिक, ऊन और ऊनी निर्धान
संवर्धन परिषद् (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई.पी.सी.) नई दिल्ली द्वारा किया
जाएगा। लेकिन सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाना होगा। इस योजना
के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों को भूवियों परिधान
निर्यात संवर्धन परिषद् और डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई.पी.सी. के पास उपलब्ध है।
सरकार को यह अधिकार होगा कि योजना के प्रणालित के लिए अधिकरणों
के संबंध में जहाँ और जैसा उचित समझे परिवर्तन कर सकती है।

(2) निर्यात हकदारी केवल उन निर्यातकों के लिए ही अनुभव होगी
जो सश्रम पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं।

3. आर्बेटन की प्रणाली और मात्रा

(1) यदि विवाराधीन वर्ष के पहले के प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान
निर्यात चिह्नित स्तर से लगातार 91% या अधिक होता है तो कुछ

श्रेणियों की सुपर फास्ट श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उदाहरण-वर्ष 1988 वर्ष के लिए 1984, 1985 और 1986 का निर्यात रिक्वांट संश्लेषित होगा। बरख आयुक्त इन श्रेणियों को वर्गीकृत और अधि-रक्षित करेंगे।

(2) सुपर फास्ट श्रेणी के अधीन निर्यात के लिए मात्रा का 85% प्रत्येक के सामने उल्लिखित दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार रक्षित किया जाएगा :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का %
(क) भूतकालीन निष्पादन (पीपीई)	70
(ख) विनिर्मिता निर्यातक (एम ई ई)	10
(ग) केन्द्रीय/राज्य निगम	2
(घ) बिना कोटे वाले निर्यातक	3
	85

(3) सुपरफास्ट श्रेणी की शेष 15% मात्रा के लिए जो आजकल कुल निर्यात के 5% संलग्न है, लघु पैमाना उद्यमों सहित नए निर्यातकों को हविषाएं प्रदान करने के साथ-साथ उसका आबंटन खुली संविदा प्रणाली के अधीन किया जाएगा। इसे प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जा रहा है।

(4) सुपरफास्ट श्रेणी से इतर श्रेणियों के लिए, निर्यात के लिए मात्रा का आबंटन प्रत्येक के सामने संकेतित दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का %
(क) भूतकालीन निष्पादन	65
(ख) पहले आए तो पहले पाए (लघु आदेश)	
[एफ सी एफ एस (एस एम)]	20
(ग) विनिर्मिता निर्यातक (एम ई ई)	10
(घ) केन्द्रीय/राज्य निगम	2
(ङ) बिना कोटे वाले निर्यातक	3
	100

(5) हवाय उद्यम और जैसे उचित समझे उसे द्विपक्षीय समझौते के तहत उद्योग का उद्देश्य करने का अधिकार होगा।

4 आबंटन वर्ष का विभाजन तथा अवधियों के बीच मात्रा का संविभाजन

(1) पी पी ई, एम ई ई और एन यू ई प्रणाली के मामले में, वर्ष को दो अवधियों में बांटा जाएगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मई तक और दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। किए गए कुल आबंटन का कम से कम 50% प्रथम अवधि के अन्तर्गत उद्योग में लाया जाना चाहिए। शेष 50% का उपयोग द्वितीय अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। प्रत्येक अवधि के अन्त में कोई भी अप्रयुक्त बची हुई मात्रा स्वतः ही अभ्यापित हो जाएगी। लेकिन नीचे उल्लिखित पैरा 18 (2) के उपबन्धों के अनुसार आबंटन रक्षित किया जाए।

(2) (1) केन्द्रीय/राज्य निगम (2) सुपरफास्ट के रूप में वर्गीकृत लघु श्रेणियों के लिए, खुली संविदा प्रणाली (3) एफ सी एफ एस (लघु आदेश) प्रणाली के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांटा जाएगा अर्थात् बुर्न हुई और सलाई से बुर्न नहीं दोनों के लिए जनवरी-मई और जून-सितम्बर। केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली, संविदा प्रणाली और एफ सी-

एफ एस (लघु आदेश) प्रणाली के अधीन मात्रा दो अवधियों में 70:30 के अनुपात से बांटी जाएगी। वार्षिक स्तर का 70% प्रथम अवधि में और शेष 30% द्वितीय अवधि में आवंटित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए प्रथम अवधि की लक्षित मात्रा खुली संविदा प्रणाली और एफ सी एफ एस लघु आदेश प्रणाली में 1 जनवरी को खोली जाएगी। निर्यातों को स्टेगर करने के उद्देश्य से अन्य कोटे के देशों के लिए मात्राएं 15 जनवरी से खोली जाएंगी।

(3) उपर्युक्त प्रतिशत को विदेशी बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार पुनः समीक्षा कर सकती है।

5. खण्डों को आरक्षित रचना

(1) एफ सी एफ एस (लघु आदेश) प्रणाली खुली संविदा प्रणाली के लिए सुपर फास्ट श्रेणी और केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली के मामले में जहाँ पर आबंटन सलाई से बुने हुए पोशाकों को बुनी हुई (बोवन) पोशाकों के साथ मिला दिया जाता है वहाँ पर उपर्युक्त वार्षिक स्तर की 10% को मात्रा मनाई न बुनी हुई पोशाकों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

(2) वस्त्रों की पोशाकों के लिए अंतिम निधि को सभी श्रेणियों में उपलब्ध मात्राओं का 10% सुरक्षित रखा जाएगा।

(3) उनी पोशाकों के लिए यह आरक्षण विशिष्टिकृत देशों और श्रेणी की मात्राओं की शर्त के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में नीति की घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

6. भूतकालीन निष्पादन प्रणाली

(1) भूतकालीन निष्पादन हकदारी की परिगणना करने के लिए अधिकरण :— प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा की हकदारी की गणना के लिए अधिकरण वस्त्र परिधान निर्यातक संवर्धन परिषद ए ई पी सी, नई दिल्ली होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में ए ई पी सी के कार्य का सर्वेक्षण करेगा।

(2) भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए मात्रा पद्धति :— 1984 वर्ष के लिए भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अधीन कोई निर्यातक मात्रा से आबंटन के लिए केवल तब पात्र होगा जबकि उसने दो वर्षों अर्थात् 1985 और 1986 में से किसी भी एक वर्ष के दौरान संबंधित देश/श्रेणी में वास्तविक पोतलघान द्वारा निर्यात निष्पादन किया हो। बाद के 1989 और 1990 वर्षों के लिए, पी पी ई की परिगणना के लिए आधार अवधि क्रमशः 1986 और 1987, 1987 और 1988 होगी।

(3) आधार अवधि और सीलिंग :— 1988 के लिए भूतकालीन निष्पादन हकदारी, 1985 और 1986 की आधार अवधि के दौरान निर्यात के औसत मूल्य के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के युगानुगत के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। बाद के 1989 और 1990 वर्षों के लिए आधार अवधि क्रमशः 1986-87 और 1987-1988 होगी। भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपात आबंटन प्रत्येक देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान निर्यातक के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के बराबर अधिकतम उच्चतम सीमा के अधीन होगा। किसी भी व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में बाद में होने वाले निर्यातों को परिवर्धन के मामले में रथ नुगत मात्रा की पूर्ण प्रतियां दहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन निर्यातक की हकदारी में उचित समंजन कर दिया जाएगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण :— भूतकालीन निष्पादन हकदारी संगत वर्ष की 30 सितम्बर तक किसी भी समय या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पोशाकों के अन्य वंजीकृत निर्यातक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जा सकती है।

(क) भूतकालीन निष्पादन हकदारी के सभी हस्तांतरण केवल हस्तांतरी द्वारा 10 प्रतिशत बैंक गारण्टी करने पर ही अनुमित किए जाएंगे।

(ख) हस्तांतरों को हस्तांतरित मात्रा के निर्यात के लिए 60 दिन का संगत अवधि जिसमें हस्तांतरण किया गया है उसकी अंतिम तिथि तक जो भी पहले हो, की अनुमति दी जाएगी।

(ग) जिस निर्यातक ने अपनी हकदारी एक विशेष देश/क्षेत्रों में दूसरे निर्यातक को हस्तांतरित की हो, वह उसी देश/क्षेत्रों में किसी अन्य निर्यातक से भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण पूर्ण या आंशिक रूप में मांगने के लिए पात्र नहीं होगा।

(घ) जिस निर्यातक ने पूर्ण या आंशिक रूप में विशेष देश/क्षेत्रों में किसी अन्य निर्यातक से हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है तो वह उसी देश/क्षेत्रों में अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी का ही हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ङ) भूतकालीन निष्पादन का हकदार व्यक्ति जो किसी देश/क्षेत्रों में खुली संचिका "पहले" आए सो "पहले पाए" के लघु आदेशों की पद्धति के अंतर्गत किसी हकदारी को प्राप्त करता है, वह इस प्रकार के छोटे आदेशों की हकदारी प्राप्त करने के बाद उन देश/क्षेत्रों में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(च) हस्तांतरों के पास हस्तांतरित हकदारियों अन्य सभी प्रकार से ऊर्ध्व नियम और शर्तों के अधीन होंगी, जो हस्तांतरण के लिए लागू हैं।

7. सुपरफास्ट क्षेत्रों के लिए खुली निबिदा पद्धति

(1) इस पद्धति के अधीन अन्य निबिदाओं के आधार पर मात्राएं आबंटित की जाएंगी। निर्यातकों को आवेदित मात्रा पर सरकार की प्रस्तुत किए गए प्रीमियम को दर्शाते हुए अन्य निबिदाएं भेजनी होंगी। आवेदन-पत्र शस्त्र आयुक्त द्वारा घोषित किए जाने पर सीलिंग मात्रा के अन्तर्गत भेजे जाएंगे।

(2) आबंटन भेजे गए प्रीमियम के आधार पर निश्चय किया जाएगा और उस दिन जबकि उपलब्ध मात्राएं अधिक से अधिक हैं तो पावता का निर्णय उच्च प्रीमियम बोली के आधार पर होगा।

(3) निर्यातकों को न्यूनतम निर्यात मूल्य पर मात्रा का निर्यात करना अपेक्षित होगा जो कि सरकारी बोली तथा निर्यातकों द्वारा दिए गए 3 प्रीमियम को मिला कर होगा। सरकारी बोलीगत वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में औसतन एक मूल्य बनूँ के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(4) इस पद्धति के अधीन आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(क) निर्यातकों को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत होना चाहिए (अथवा ऊनी बुने हुए वस्त्रों के लिए ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्)।

(ख) एक निर्यात से एक दिन के लिए एक देश/क्षेत्रों के लिए केवल एक ही आवेदन-पत्र अनुमेष होगा। लेकिन, एक से अधिक आवेदन पत्र दिया जा सकता है बशर्ते कि इन आवेदन-पत्रों में दी गई कुल मात्रा वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चय की गई अनुबद्ध मात्रा सीलिंग के अन्तर्गत है।

(ग) इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। दूसरी अवधि में आबंटन 60 दिनों के लिए अथवा संबद्ध वर्ष के 31 दिसम्बर तक इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगा।

(घ) आबंटन के लिए आवेदन-पत्रों के साथ परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् को देय कुल प्रीमियम धनराशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट लगा होना चाहिए।

(ङ) सभी पंजीकृत निर्यातक चाहे उनकी अन्य हकदारियां किसी भी अन्य पद्धति के अधीन कुछ भी हो, बोली के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

8. पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) पद्धति:

इस पद्धति के अन्तर्गत मात्रा का आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संचिकाओं और संचिकाओं द्वारा समायित आवेदन पत्रों के भेजे किया जाएगा। लेकिन संचिका आवश्यकता पड़ने पर केवल प्रमाणन के समय पर ही प्रस्तुत करना होगा। मात्रा का आबंटन केवल लघु आदेशों के लिए किया जाएगा जो कि विभिन्न देश/क्षेत्रों के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा परिणामात्मक सीमाओं के भीतर नियत किए गए हों। ऐसी परिणामात्मक सीमाएं उचित समय के भीतर घोषित कर दी जाएंगी। इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(1) निर्यातकों को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (या सलाई से बने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के साथ) आवेदन पत्र के दिन पंजीकृत होना चाहिए।

(2) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/क्षेत्रों के लिए केवल एक आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक, लेकिन आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे आवेदन पत्रों में आने वाली मात्रा निर्धारित मात्रा सीमा के भीतर हों।

(3) इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। दूसरी अवधि में आबंटन केवल 60 दिन या संगत वर्ष की 31 दिसम्बर इसमें से जो भी पहले हो, तक वैध होगा।

(4) आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर मंजूर किया जाएगा, और जिस दिन उपलब्ध मात्रा अतिपूर्वकीत हो जाएगी, उस दिन पावता का निर्णय उच्च हकई मूल्य बनूँ के आधार पर किया जाएगा।

(5) भूतकालीन निष्पादन हकदारी मात्रा निर्यातक संबंधित देश/क्षेत्रों के लिए पैरा 6(3) के अनुसार यथा परिकल्पित अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद इस पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उसके लिए भूतकालीन हकदारी के समस्त शेष अन्वयित करने का भी विकल्प होगा कि वह संबंधित देश/क्षेत्रों का है और तब वह पहले आए सो पहले पाए (छोटे आदेशों) के अन्तर्गत आवेदन करता है बशर्ते कि उसने उस देश/क्षेत्रों में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी भी प्रकार का हस्तांतरण नहीं किया है।

(6) विनिर्माता-निर्यातक हकदारी के धारक को पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र बनने से पूर्व अपनी ऐसी हकदारी का पूरा-पूरा उपयोग करना पड़ेगा या उसे अन्वयित करना पड़ेगा।

(7) पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) पद्धति के अन्तर्गत आबंटन के उद्देश्य के लिए आवेदक इस संबंध में एक सपथपत्र देना क आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985-88 के पैरा 120 में यथापरिभाषित उच्चकी किसी भी सहयोगी ने इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया है और यह कि उसके स्वामित्व के अधीन किसी अन्य स्वामित्व वाली व्यापार संस्था ने भी आबंटन के लिए इस पद्धति के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है। आगे, प्रथम अवधि के आबंटन के लिए आवेदक इस संबंध में भी सपथ पत्र देंगे कि उनका कोई भी सहयोगी व्यापार संस्था कोई भी भूतकालीन निष्पादन हकदारी नहीं रखती है। तथापि, उचित प्रपत्र में एक समय दिए गए सपथपत्र तथा एक देश अथवा देशों के समूह को भी लिया जा सकता है जिसमें आवेदक इंगित करेगा कि एक अथवा देशों के समूह के लिए प्रथम आए प्रथम पाए (लघु आदेश) प्रणाली के अन्तर्गत अकेला आवेदन करेगा।

9. विनिर्माता निर्यात पद्धति :

(1) इस पद्धति में वार्षिक स्तर की 10 प्रतिशत तक की मात्रा विनिर्माता निर्यातक को आबंटित की जाएगी।

(2) वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों को वार्षिक स्तर का 8 प्रतिशत आबंटित किया जाएगा। 3 प्रतिशत का स्तर उन नए निर्यातकों के लिए आरक्षित होगा जो संगत वर्ष के दौरान विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करते हैं।

(3) इस पद्धति के अधीन आबंटन हेतु पात्र होने के लिए नए विनिर्माता निर्यातकों को कम से कम 100 मशीनें और 150 कारीगरों को रखा जाना चाहिए।

(4) इस पद्धति के अधीन आबंटन के लिए वर्तमान विनिर्माता वस्त्र आयुक्त के पास यथापंजीकृत अपनी वर्तमान विनिर्माण क्षमता के आधार पर पात्र होंगे। लेकिन, उनको 1989 तक कम से कम 100 मशीनें और 150 कारीगर लगाकर अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना भी चाहिए। वर्तमान विनिर्माताओं के लिए इस पद्धति के अधीन आबंटन के लिए पात्रता मानदण्ड 1 जनवरी, 1989 को 100 मशीनें और 150 कारीगर होंगे।

(5) वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों के लिए 50% का आरक्षित स्तर भूतकालीन निष्पादन के आधार पर आबंटित किया जाएगा और शेष 50% विनिर्माता निर्यातकों की विनिर्माण क्षमता के आधार पर होगा। भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक पद्धति के अधीन विनिर्माता निर्यातक के लिए कुल आबंटन आधार अवधि के दौरान (उदाहरणार्थ 1988 के दौरान आबंटन के लिए 1985 और 1986) उनकी घासतन वार्षिक निर्यात निष्पादन का 100% से अधिक नहीं हो। निर्यातक को विनिर्माता निर्यातक हकदारी का कुल आबंटन उसकी विनिर्माता क्षमता से भी अधिक नहीं होगा।

(6) नए विनिर्माता निर्यातकों के लिए आबंटन इनकी विनिर्माता क्षमता के आधार पर किया जाएगा। नए विनिर्माता निर्यातकों के लिए आरक्षित वार्षिक स्तर का 2% में से आबंटित मात्राएं पहले उन वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों के लिए आबंटित होंगी जिनके पास 100 मशीनों से अधिक होते हुए उनकी विनिर्माण क्षमता में कुल मिलाकर कमी हुई है।

(7) वस्त्र आयुक्त इस पद्धति के अधीन आबंटन के लिए पात्रता का फैसला करेगा जिसके लिए वह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

10. केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली :

केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और केन्द्रीय/राज्य स्तरों की शिखर सहकारी हथकरघा विपणन समितियों के लिए वार्षिक स्तर के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत का वित्त आबंटन किया जाएगा। लेकिन यह आबंटन इन निगमों/उच्च स्तरीय समितियों द्वारा केवल सीधे निर्यातों के लिए होगा। इस प्रणाली के अधीन आबंटन इस शर्त के अधीन होगा कि केन्द्रीय/राज्य निगमों को अपने संरक्षण में उत्पादन करना चाहिए। निगम/शिखर समितियाँ भी पूर्व निष्पादन और आबंटन के पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेश की पद्धतियों के अधीन मात्रा के आबंटन के लिए नीति में दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन पात्र होंगी। वस्त्र आयुक्त निगमों/शिखर समितियों की हकदारी निश्चित करेगा। ऐसे निगम अपने विनिर्माण एककों को जिनके पास 1 जनवरी, 1989 से कम से कम 100 मशीनें और 150 कारीगर हों, केवल 1989 में इस कोटे के आबंटन के लिए पात्र होंगे।

11. बगैर कोटा निर्यातक पद्धति :

(1) बगैर-कोटा देशों के निर्यात और कोटा देशों को गैर-कोटा मर्चों के निर्यात में प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र के गैर-कोटा देशों और कोटा-देशों के गैर कोटा मर्चों में निर्यातकों को आबंटन के लिए 20 (बीस) लाख रुपये को निर्यात निष्पादन के साथ आबंटन

के लिए वार्षिक स्तर का 3 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा।

(2) इस पद्धति के अधीन हकदारी की गणना के प्रयोजनार्थ जुलाई, 1986 से जून, 1987 की अवधि के लिए निर्यात निष्पादन 1988 के दौरान और 1987-88 एवं लगातार दो वर्ष 1988-1989 के लिए उसी अवधि के लिए आबंटन को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) इस पद्धति के अधीन निर्यातक का भाग उसके निर्यातों के यथा-अनुपात मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा जो कि आधार अवधि दौरान (उदाहरणार्थ 1988 वर्ष के लिए जुलाई 1986-जून 1987) नान कोटा सामान्य मुद्रा क्षेत्र देशों को और कोटा देशों को नान कोटा मर्चें संगत वर्ष में तदनुसार अवधि के साथ तुलना में उसकी निर्यात के मूल्य में वृद्धि द्वारा समंजित होगा। इस यथा-अनुपात पर आधारित भाग विभिन्न श्रेणियों में निर्यातक को आबंटित की गई मात्रा का हल निकालेगा।

(4) आबंटन के लिए निर्यातक अधिकतम 15 देश/श्रेणियों के समूह को पसन्द करने के लिए अनुमति दिया जाएगा।

(5) सभी अन्य शर्तें भूतकालीन निष्पादन हकदारी प्रणाली के समान होंगी।

12. मंद गति वाली मर्चें:

मंद गति वाली मर्चों को अभिजात करने के लिए संगत वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान और सम्पूर्ण वर्ष के दौरान का निष्पादन हिसाब में लिया जाएगा। (1988 के लिए 1987 के प्रथम चार महीनों के दौरान और संपूर्ण 1986 वर्ष संगत होगा।) वह मंद गति वाली समझी जाएगी जिसका निर्यात संदर्भित अवधि के दौरान प्रथम चार महीनों के लिए अथवा पूर्ण वर्ष की संदर्भ अवधि के दौरान चिह्नित स्तर का 75% से अधिक न हो। लेकिन, सरावर वर्ष के दौरान मानदण्ड के परिवर्तन करने का अधिकार रखती है यदि मांग का रुख और वार्षिक स्तर की उपयोगिता की गति न्यायसंगत है।

इस सार्वजनिक सूचना में अन्यत्र दी गई किसी अन्य बात के होते हुए भी मंद गति के रूप में घोषित मर्चों के संबंध में निम्नलिखित कुछ होगी :—

(1) उच्चतर नए वस्त्र अनिवार्य नहीं होगा।

(2) निर्यातक को सामान्य बैंक गारण्टी/पेशगी धनराशि के स्थान पर एक प्रतिशत पेशगी धनराशि/बैंक गारण्टी भेजनी होगी।

(3) पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) के लिए आवेदन पत्र के मामले में निर्धारित मात्रिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। लेकिन, यदि कोई आवेदक मंद गति वाली मर्चों के आबंटन में जो कि तेज गति वाली मर्चों की निर्धारित सीमा से दस गुना अधिक होगी तो उसको तेज गति वाली मर्चों के लिए अर्पित सामान्य बैंक गारण्टी और साखपत्र प्रस्तुत करना होगा। एक देश/श्रेणी में एक ही दिन में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की संख्या पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यदि ऐसी मर्चों के लिए मांग उपलब्धता से अधिक है तो सरकार को मात्रिक सीलिंग के अन्तर्गत वितरण करने का अधिकार है और कोई अन्य शर्तें जिसको सरकार आवश्यक समझे हकदारी के उचित वितरण के लिए लागू कर सकती है।

(4) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत सदान बिलों का सत्यापन मंद गति वाली मर्चों के लिए 60 दिन तक वैध होगा।

(5) मंद गति वाली मर्चों के लिए अलग म्यूनतम मूल्य हो सकता है।

- (6) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों के संबंध में मंद गति वाली मदों के लिए पैरा 8(7) में उल्लिखित शर्तें लागू नहीं होंगी।

13. उन श्रेणियों का आबंटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विशिष्ट सीमा के अधीन नहीं है:--

ऐसी श्रेणी के अधीन विशिष्टीकृत मात्रा जो विशेष सीमा की शर्तों के अधीन नहीं आती किन्तु यू.एस.ए. के सारे ग्रुप-2 की सीमा के अधीन आती है का आबंटन सभी पद्धतियों के अधीन किसी अन्य श्रेणी की ही भांति किया जाएगा। उपर्युक्त पद्धति के अधीन संवेदनशील मदों के आबंटन के लिए लागू सभी शर्तें ऐसी श्रेणियों के लिए भी लागू होंगी। ऐसा आबंटन ऐसी उन सभी शर्तों के अधीन होगा जो इनमें से किसी भी श्रेणी के निर्यात शुरू करने की दिशा में निर्धारित की जाए। ऐसे निर्यात के अन्तर्गत आने वाली मदों में भूतकालीन निष्पादन हकदारी और निर्यात-विनिर्माता में परिवर्तन और अनिवार्य मदों में भी उचित परिवर्तन के आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति समूह सीमा के अधीन दी जा सकती है।

14. हथकरघा वस्त्रों के लिए विशेष आरक्षित मात्रा का आबंटन :

"पहले आए सो पहले पाए" (लघु आदेश) पद्धति तथा केन्द्र/राज्य निगम प्रणाली के अधीन 90:10 के अनुपात में यू.एस.ए. ई.ई.सी. के सदस्य राज्य, नावों तथा फिनलैंड के लिए हथकरघा वस्त्रों की विशेष आरक्षित मात्रा का आबंटन किया जाएगा।

15. न्यूनतम निर्यात (न्यूनतम) मूल्य:--सामान्यतः प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए सामान्यतः केवल एक न्यूनतम मूल्य होगा तथापि बोमी गति वाली मदों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। जहां व्यक्तियों के वस्त्रों का परिवर्तन बच्चों की अपेक्षा अधिक संख्या में है वहां बच्चों के वस्त्रों के लिए कम मूल्य अनुमित है। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेंगे। उनको निर्धारित करने समय वे उन सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देंगे जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक को मंद गति वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं।

16. निर्यात हकदारी के स्थापन की वैधता अवधि:--जहां वैधता अवधि 60 दिन प्रतिबंधित होगी लदान बिल पर स्थापन स्वतंत्र संविदा प्रणाली पहले आए तो पहले पाए छोटे आदेश पद्धतियों के मामले में अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

17. साखपत्र:--सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आबंटन साखपत्र की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। साखपत्र प्रचलित वैध और अपरिवर्तनीय होने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में साखपत्र, आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सभी आबंटन प्रणालियों के मामले में साख पत्र प्रमाणन के समय प्रस्तुत किए जाएं। मंद गति वाली मदों के लिए साखपत्रों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरा 12(1) में दिया गया है। किसी अन्य पार्टी द्वारा किया गया पोतलदान अनुमित नहीं है।

18. पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी और उनका जवत करना :

(1) भूतकालीन निष्पादन पद्धति विनिर्माता/निर्यातक पद्धति और गैर कोटा निर्यातक पद्धति के मामले में निर्यात को पेशगी धन या बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसे 31 मई को इससे पहले आबंटन का 50 प्रतिशत उपयोग तथा बाकी 50 प्रतिशत का उपयोग 30 सितम्बर तक कर लेना चाहिए। नीचे पैरा 2 में दिए गए के सिवाए किसी भी अवधि में उपयोग किया गया भाग स्वतः समर्पित समझा जाएगा।

(2) भूतकालीन निष्पादन हकदारी, विनिर्माता निर्यातक हकदारी तथा नान-कोटा निर्यातक हकदारी की वैधता 30 सितम्बर तक प्रतिबंधित होगी। लेकिन यह वैधता जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत

की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन साखपत्र द्वारा समर्थित विशेष ठेकों के लिए 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा सकती है।

(3) पहले आए सो पहले पाए (लघु आदेश) प्रणाली, संविदा प्रणाली और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में, निर्यातक को आवेदित मात्रा के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी द्वारा समर्थित निष्पादन बांड देना होगा।

(4) भूतकालीन निष्पादन पद्धति विनिर्माता निर्यातक पद्धति और गैर कोटा निर्यातक पद्धति के मामले में एक निर्यातक जो संविदा प्रणाली पहले आए सो पहले पाए तथा केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली या उपयुक्त पैरा-2 में उल्लिखित पूर्ववर्धितकरण अवधि के दौरान एक विशेष अवधि के अन्तर्गत निर्यात हकदारी का 100 प्रतिशत से कम निर्यात करता है उसकी पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी जवत हो जाएगी। एक निर्यातक जो 75 प्रतिशत तक लेकिन 100 प्रतिशत से कम निष्पादन करता है उसका अनुपातिक जवत किया जाएगा। यदि निर्यात हकदारी आबंटन का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यात की पूरी ई.एम.डी./बैंक गारंटी जवत की जाएगी।

(5) ये प्रावधान जब भी लागू होंगे, अनिवार्य बढ़ता की शर्त के अधीन होंगे।

(6) मंद गति वाली मदों के लिए पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी पैरा 12 (3) और (4) में यथा उल्लिखित लागू होगी।

(7) केन्द्रीय राज्य निगमों के मामले में जहां उपयोग वैधता अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम नहीं है, निर्यातक को निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर अगले आबंटन अवधि के लिए समय वृद्धि लेनी होगी। ऐसी समय वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध आबंटन अवधि के अन्त से एक मास के भीतर दाखिल करने चाहिए। ऐसे मामलों में, निर्यातकों को शेष मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर पेशगी धन-राशि जमा करनी होगी। बैंक गारंटी देनी होगी। पूर्ण रूप से निर्यात करने में असफल होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी पूरी तरह जवत हो जाएगी।

(8) वे व्यक्ति जिन्हें कोटे आवंटित किए जाते हैं, किन्तु वे उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो इस संबंध में जो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उन्हें और अगले कोटा देने से अग्रत घोषित कर दिया जाएगा।

19. पेशगी की धनराशि/बैंक गारंटी जवत करने के विरुद्ध अपील:--आबंटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी के जवत करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। परिवान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप बैंक गारंटी जवत किए जाने पर संबद्ध निर्यातक ऐसे जस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बम्बई को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे। यदि किसी मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र मंत्रालय को जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गई समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

20. 30 सितम्बर से उपलब्ध मात्रा को शामिल करना:--इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी अन्य स्थान पर निहित किसी भी नियम को ध्यान में रखे बिना ही 30 सितम्बर को उपलब्ध शेष मात्रा, चाहे वह बिना स्तरों से या सम्पूर्ण से प्राप्त हो, एक सामान्य समूह में मिलाई गई समझी जाएगी और विभिन्न विभागों के लिए किसी आरक्षण

के बिना उस गति वर्ग के लिए संविदा प्रणाली तथा पहले हुए भी पाए गए लघु आवेदन पद्धति के अधीन उस मात्रा को बांटा जाएगा।

21. निर्यात हकदारी आर्बटन का पर्यवेक्षण:—वास्तव आयुक्त, सम्बन्धी निर्यात हकदारी के आर्बटन से संबंधित मामलों पर दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा। एक समन्वय समिति जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे, और सम्बन्धित निर्यात संबंधित परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, समय-समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेंगे। विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

22. सीमा-शुल्क द्वारा निकासी :

(क) निर्यात के अधीन उत्पाद जिनमें से नीचे भी शामिल हैं जो यू.एस.ए. में विनिर्मित सीमा के अधीन न हों।

पोतलदान की अनुमति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्रों पर परिधान निर्यात संबंधित परिषद द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए मूल पोत-परिचालन पत्रों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठंकन के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद:—जहां तक कनाडा की निर्यातित मर्चों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों, टेलर काटर्ड कमीजों के सिवाय और आस्ट्रिया की सूती हथकरघा पोशाकों यू.एस.ए., ई.ई.सी., नार्वे, फिनलैंड के लिए निर्यातित वर्ग के कुछ हथकरघा वस्त्रों के लिए आरक्षित मात्रा को निर्यात का संबंध है, बड़ी सीमा-शुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कम्बिनेशन प्रपत्र के भाग-2 में निरीक्षण पृष्ठंकन के आधार पर दी जाएगी।

(ग) "भारतीय मर्चों" के अधीन आने वाली मर्चें:—उन भारतीय मर्चों के बारे में जो कि डेड भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं यू.एस.ए., यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, फिनलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, नार्वे और कनाडा की निर्यात के लिए पोतलदान सीमा-शुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण-पत्रों के आधार पर अनुमति किया जाएगा।

23. (क) निर्यात प्रमाण-पत्र, उद्योग प्रमाण पत्र और बीसा:—संगत द्विपक्षीय समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण-पत्र परिधान निर्यात संबंधित परिषद या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे:—

1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय:—

(क) निर्यात के अधीन सभी पोशाक/बुनी हुई मर्चों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्योग प्रमाण-पत्र।

(ख) सभी गैर निर्यातित पोशाकों/बुनी हुई मर्चों के लिए उद्योग प्रमाण-पत्र।

2. फिनलैंड:—निर्यातित मर्चों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

3. स्वीडन:—निर्यातित मर्चों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र।

4. आस्ट्रिया:—निर्यात या निर्यात की शर्त के अधीन पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

5. नार्वे:—उन श्रेणियों के संबंध में जो विनिर्मित सीमाओं के अन्तर्गत आती हैं के लिए भी निर्यात प्रमाण पत्र और मूलतः प्रमाण-पत्र।

6. कनाडा:—बुने हुए, पावरलूम, और मिल-निर्मित मूल की पोशाकों जो निर्यात के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कनेक्शन शालर मूल्य के परेषण के लिए, निर्यात प्रमाण पत्र।

7. यू.एस.ए.:—(क) यू.एस. डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए बीसा।

(ख) यू.एस. डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाकों, बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाण-पत्र।

(ग) हथकरघा प्रमाण-पत्र:—निर्यातित मर्चों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों, टेलर काटर्ड कमीजों के सिवाय के कनाडा और सूती हथकरघा पोशाकों के आस्ट्रिया ई.ई.सी., नार्वे, फिनलैंड के लिए निर्यातित वर्ग के कुछ हथकरघा वस्त्रों के लिए आरक्षित मात्रा को निर्यात के मामले में, ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौतों में निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्त्र समिति प्रमाण-पत्र जारी करेंगी।

24. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपबन्ध का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

25. संवद्ध निर्यात संबंधित परिषद और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त के कार्यालयों के पते निम्न प्रकार से हैं:—

1. परिधान निर्यात संबंधित परिषद, सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 58 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019।
2. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद, 612/714, प्रणोक इस्टेट, 24 बाराकम्बा रोड, नई दिल्ली-110001।
3. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं.-11500, बम्बई-400020।
4. वस्त्र समिति, क्रिस्टल, 79, डा. एनी बिमेंट रोड, बम्बई-400018।
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वेस्ट ब्लॉक, 7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022।

ह./-

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

एच.सी. भाजाव,
निर्यातक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th October, 1987

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 28-ETC(PN)/87

Subject :—Scheme for export under OGL 3 of garments and knitwear to USA, EEC member states, Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada from 1st January, 1988 to 31st December, 1990.

F. No. 2/95/87-E-I.—This scheme relates to the exports of certain readymade garments and knitwear items to USA, EEC Member States (FRG, France, Italy, Benelux, U.K., Irish Republic, Denmark, Greece, Portugal and Spain), Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada for the period 1st January, 1988 to 31st December, 1990.

2. Agencies for Administration of the Scheme.—

(i) Unless otherwise directed the Apparel Export Promotion Council, New Delhi will allocate export entitlements and do the necessary certification for the export of all garments and knitwear covered by this scheme, except that the entitlements for woollen knitwear would be allocated by the Wool and Woollen Export Promotion Council (W&WEPC), New Delhi. However in respect of woollen knitwear necessary certification will continue to be done by the Apparel Export Promotion Council.

List of categories of textile products covered under this scheme are available with the Apparel Export Promotion Council and W&WEPC.

(ii) Government reserves the right to make changes, as and when considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the scheme.

(iii) Export Entitlements will be allowed only to exporters who are registered with the competent registering authorities.

3. System and Quantum of Allotment.—(i) Certain categories will be identified as superfast categories, if, the exports were consistently 91 per cent or more of the level earmarked during each of the three years preceding the year under consideration. For example, for the year 1988, performance during the years 1984, 1985 and 1986 will be relevant. Textile Commissioner will identify and notify these categories.

(ii) 85 per cent of the quantities for exports under superfast categories will be allocated according to

the following system at rates indicated against each of them :

System	Percentage of annual Level
(a) Past Performance (PPE)	70
(b) Manufacturer Exporter (MEE)	10
(c) Central/State Corporation	2
(d) Non Quota Exporters (NQE)	3
	<hr/> 85 <hr/>

(iii) For the remaining 15 per cent of the superfast categories, which works out to roughly 5 per cent of the total exports, at present, allocation will be made, under the Open Tender System, in order to inter alia provide opportunities to new exporters including small scale entrepreneurs. This is being introduced on an experimental basis.

(iv) For categories other than superfast categories, quantities for export will be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them :—

System	Percentage of annual Level
(a) Past Performance (PPE)	65
(b) First-Come-First-Served (Small Order) [(FCFS (SO)]	20
(c) Manufacturer Exporters (MEE)	10
(d) Central/State Corporation	2
(e) Non Quota Exporters (NQE)	3
	<hr/> 100 <hr/>

(v) Government reserves the right to use flexibilities provided in the Bilateral Agreements as and when considered appropriate.

4. Division of the Allotment year and Appointment of Quantities among periods.—(i) In the case of PPE, MEE and NQE Systems, the year will be divided into two periods. The first period will be from 1st January to 31st May and the second period will be from 1st June to 30th September. A minimum of 50 per cent of the total allotment made should be utilised within the first period. The remaining 50 per cent should be utilised during the second period. Any unutilised balance at the end of each period

shall stand automatically surrendered. The allotment may however be made valid beyond 30th September as per provisions in para 18(ii) below.

(ii) In the case of (i) Central/State Corporation, (ii) Open Tender System for certain categories identified as superfast and (iii) the FCFS (Small Order) System, the year will be divided into 2 periods, namely January—May and June—September for both woven and knitted items.

Quantities under the Central/State Corporation System, Open Tender System and FCFS (Small Order) System will be distributed among the two periods in the ratio of 70 : 30. 70 per cent of the annual level will be allotted in the first period and the remaining 30 per cent in the second period. In the Open Tender System and FCFS Small Order System, quantities for USA and Canada earmarked for the first period will be opened on 1st January. Quantities for other quota countries will be opened on 15th January in order to stagger the exports.

(iii) The above percentages may be re-adjusted by the Government depending upon trends in the overseas markets.

5. Reservation of Segments.—(i) In the case of FCFS (Small Order) System, Open Tender System for superfast categories and Central/State Corporations Systems whenever knitted garments are clubbed with woven garments for allocation, 10 per cent of the annual level available would be reserved for knitted garments.

(ii) Eligibility for Past Performance Entitlement quantities available in all categories at the terminal dates will be reserved.

(iii) For woollen garments there will be reservation in terms of quantity in specified countries and categories. The policy in this regard will be announced by the Textile Commissioner.

6. Past Performance System.—(i) Agency for Calculation of Past Performance Entitlements.—The agency for calculation of the entitlement of quantities under Past Performance System in respect of each exporter will be AEPC, New Delhi. Textile Commissioner will supervise this work of AEPC.

(ii) Eligibility for Past Performance Entitlement System.—An exporter will be eligible for allotment of quantities under the Past Performance system for the year 1988 only if he has export performance by way of actual shipments in the relevant country/

category during any one of the two years viz., 1985 and 1986.

For the subsequent years 1989 and 1990, the base periods for calculating PPE would be 1986 and 1987, 1987 and 1988 respectively.

(iii) Base Period and Ceiling.—The Past Performance Entitlement for 1988 will be determined for each country/category combination pro-rata on the basis of average value of exports during the base period of 1985 and 1986. For subsequent years 1989 and 1990, the base periods would be 1986-87 and 1987-88 respectively. The pro-rata allotment of Past Performance Entitlement will be subject to a maximum ceiling in each country/category equal to the value realisation of the exporter during the base period divided by the average realisation during the base period. In case of any subsequent changes in the entitlement of any individual exporter, the entire exercise of pro-rata quantity need not be reopened but suitable adjustment will be made in the entitlement of the exporter.

- (a) All transfers of Past Performance Entitlement would only be allowed on submission of 10 per cent Bank Guarantee by the transferee.
- (b) Transferee would be allowed 60 days or till the last date of relevant period which transfer is effected, whichever is earlier, to export the transferred quantity.
- (c) Shipments against such transferred entitlement will be counted as the exports of the transferee.
- (d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country/category either in full or in part will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country/category.
- (e) A Past Performance Entitlement holder who obtains any entitlement under Open Tender System First Come First Served (Small Order) System in a particular country/category will not be eligible to effect any transfer from his Past Performance Entitlement in that country/category after he obtains such Entitlements.
- (f) The transferred entitlement in the hands of the transferee will be subject, in all other respects, to the terms and conditions as applicable to the transferer.

7. Open Tender System for Superfast Categories.—(i) Under this system, quantities will be allotted on the basis of sealed tenders. Exporters will have to submit sealed tenders indicating the premium offered to the Government on the quantities applied for. Applications will have to be made within the quantitative ceiling to be announced by the Textile Commissioner.

(ii) Allotments will be determined on the basis of the premium offered and on a day when the available quantities are over-subscribed the eligibility will be decided on the basis of higher premium bid.

(iii) Exporters would be required to export the goods on a minimum export price which would be the upset price plus the premium paid by the exporters. The upset price will be determined by the Textile Commissioner on the basis of the average unit value realisation in these categories during the previous year.

(iv) Allotments under this system will be subject to the following conditions :

- (a) Exporters should have been registered with the AEPC (or W&WEPC for woolen knitwear).
- (b) Only one application will be admissible from an exporter for one country/category for one day. However, more than one application can be made provided the total quantity covered by such applications is within the stipulated quantitative ceiling, fixed by the Textile Commissioner.
- (c) Allotments under this system will be valid for a period of 60 days. In the second period allotment will be valid for 60 days or upto 31st December, of the relevant year, whichever is earlier.
- (d) Applications for allotments should be accompanied by Demand Draft for the total premium amount payable to the Apparel Export Promotion Council.
- (e) All registered exporters irrespective of their other entitlements under any other System are eligible to apply for the bid.

8. First-come-first-served (Small Order) System.—Under this system quantities will be allotted on first-come-first-served basis in all categories other than superfast categories, against applications supported by firm contracts and L.C. L.C. however need be produced only at the time of certification. Allotment of quantities shall be made only for 87/1386 GI-2.

small orders which are within the quantitative limit fixed by the Textile Commissioner for different country/category. Such quantitative limits will be announced in due course. The allotment under this System will be subject to the following conditions :—

- (i) The exporters should have been registered with the Apparel Export Promotion Council (or with W&WEPC for woollen knitwear) on the day of application.
- (ii) Only one application will be admissible for an exporter for one country/category for one day. However, more than one application can be made provided the total quantity covered by such application is within the stipulated quantitative ceiling.
- (iv) Allotment will be granted on first-come-for a period of 60 days. In the second period allotment will be valid for 60 days or upto 31st December of the relevant year, whichever is earlier.
- (iv) Allotment will be granted on first-come first-served basis, and on a day when available quantities are over-subscribed the eligibility will be decided on the basis of higher unit price realisation.
- (v) An exporter with PPE will be eligible for applying under the System after exporting at least 50 per cent of his PPE in the relevant country/category as worked out according to para 6(ii). He will also have the option of surrendering the entire balance of PPE that he holds in the relevant country/category and then applying under FCFS (Small Order) System, provided he has not effected any transfer from his PPE in that country/category.
- (vi) Any MEE holder will have to utilise or surrender his full entitlement before becoming eligible for applying under the FCFS (Small Order) System.
- (vii) For the purpose of allotment under the FCFS (Small Order) System, an applicant should give an affidavit that none of his associate concerns as defined in paragraph 120 of the Handbook of Import-Export Procedures 1985-88 has applied for allotment under this System and also that no other proprietorship concern under his proprietorship has applied for allotment under this System. Further the applicants for 1st period allotment should also give an affidavit that none of their associate

concerns has any PPE. However, a one time affidavit in the appropriate form for the whole of the relevant year and applicable to a country or group of countries can also be taken in which the applicant will indicate one of the firms that will alone apply under FCFS (Small Order) System throughout the relevant year for a country or group of countries.

9. Manufacturer Exporter System.—(i) In this System quantities to the extent of 10 per cent of the annual leave will be allotted to manufacturer-exporters.

(ii) 8 per cent of the annual leave will be allotted to manufacturer-exporters. 2 per cent of the level will be reserved for new comers who set up manufacturing facilities during the relevant year.

(iii) For being eligible for allotment under this System a manufacturer-exporter should establish at least 100 machines and employ 150 workers.

(iv) The existing manufacturers will be eligible for allotment under the System on the basis of their existing manufacturing capacity, as registered with the Textiles Commissioner. However, they must also upgrade their manufacturing capacities by setting up at least 100 machines and employing 150 workers by 1989. The eligibility criterion for allotment under the System for existing manufacturers will be 100 machines and 150 workers as on 1st January, 1989.

(v) 50 per cent of the level reserved for existing manufacturer-exporters will be allotted on the basis of past performance and the remaining 50 per cent on the basis of the manufacturing capacity of manufacturer-exporters. The total allocation for a manufacturer-exporters under the Past Performance and the Manufacturer Exporter Systems should, however, not exceed 120 per cent of his average annual export performance during the base period (i.e. 1985 and 1986 for allotment during 1988). The total allotment of Manufacturer Exporter Entitlement to an exporter will also not exceed his manufacturing capacity.

(vi) Allotments to new manufacturer exporters will be done on the basis of their manufacturing capacity. Unallocated quantities from the 2 per cent of the annual level reserved for the new manufacturer-exporters will be allotted firstly to existing manufacturer-exporters having more than 100 machines to the extent of overall shortfall in their manufacturing capacity and then to other existing manufacturer.

(vii) The Textile Commissioner will decide the eligibility for allotment under this System for which he will issue detailed instructions.

10. Central/State Corporations System.—For Corporations under the central of the Central/State/Union Territory Governments and Apex Cooperative Handloom marketing societies at the Central/State levels, there will be special allocation not exceeding 2 per cent of the annual level. The allocation will however be made only for direct exports by these corporations/Apex societies. The allocation under the System will be subject to the condition that the Central/State Corporation should have its own manufacturing facilities. The Corporation/Apex societies will also be eligible for allotment of quantities under other Systems, subject to the fulfilment of conditions laid down in the policy. The Textile Commissioner will determine the entitlement of the Corporation/Apex Societies. Such Corporations will be eligible for allotment of this quota in 1989 only of their manufacturing units but at least 100 machines and 150 workers on 1st January, 1989.

11. Non-Quota Exporter System.—(i) In order to encourage exports to non-quota countries and non-quota items to quota countries 3 per cent of the annual level will be reserved for allocation to exporters with export performance of or above Rs 20 (twenty) lakhs in the GCA non-quota countries and non-quota items to quota countries.

(ii) For the purpose of calculating the entitlement under this system, export performance for the period July, 1986 to June, 1987 will be taken into account for allotment during 1988 and for similar periods of 1987-1988 and 1988-1989 for subsequent two year.

(iii) An exporter's share under this System will be determined the pro-rata value of his exports to non-quota GCA countries and non-quota items to quota countries, during the base period (e.g. July 1986—June, 1987 for the year 1988) adjusted by the increase in the value of his export when compared with the corresponding period in the previous year. Based on this pro-rata share, the quantities to be allocated to an exporter in different categories will be worked out.

(iv) An exporter will be permitted a choice up to a maximum of 15 country/category combinations for allotment.

(v) All other conditions will be the same as under PPE System.

12. Slow Moving Items.—For identification of slow moving items, performance during the first four

months of the previous year and the performance during the entire year before will be taken into account. (For 1988, the performance during first four months of 1987 and the entire year 1986 will be relevant.) An item would be termed slow moving if during the period under reference its exports have not exceeded 75 per cent of the level earmarked for the first four months or during the entire year of the reference period. Government, however, reserves the right to change the criteria during the course of the year, if warranted by the demand trend and pace of utilisation of annual levels.

Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, the following relaxations will be available in respect of items declared slow moving :—

- (i) There shall be no compulsory Letter of Credit stipulation.
- (ii) The exporter shall have to furnish 1 per cent Earnest Money Deposit/Bank Guarantee in lieu of normal Bank Guarantee/Earnest Money Deposit.
- (iii) The quantitative ceiling stipulated in the case of FCFS (Small Order) Application shall not be enforced. However, if any applicant seeks allocation in a Slow Moving item exceeding 10 times the ceiling on corresponding fast moving items, he will be required to submit the normal BG and LC required for fast moving items. There shall be no restrictions on the number of applications that can be submitted in one day in the country/category. Should the demand for such items exceed availability, the Government, has the right to distribute the same within a quantitative ceiling and any other condition which the Government may consider necessary for proper distribution of entitlement.
- (iv) Certification of shipping bills and bills of lading (Small Order) System for Slow Moving items will be valid upto 60 days.
- (v) There may be separate floor prices for Slow Moving Items.
- (vi) The conditions stipulated in para 8(vi) will not apply to Slow Moving items in respect of 100 per cent EOU's and Free Trade Zones.

13. Allocation of Categories not Subject to Specific Limit in U.S.A. and Canada.—A specified quantity under the categories not subject to specific limit but subject to overall group II limit in USA/Group-I limit in Canada will be allocated under all Systems

like any other category. All conditions applicable to allocation of sensitive items under the above Systems will also be applicable to allocation of such categories. Such allocations will also be subject to any other condition that may be stipulated in the event of limitations on exports being introduced on any of these categories. Conversion of PPE, MEE and NOE into non-restrained items using appropriate conversion factors, may be permitted within the Group ceiling.

14. Allocation of Special Quantities Reserved for Handloom Garments.—Special quantities reserved for handloom garments in USA, EEC member states, Norway and Finland will be allotted under the FFS (Small Order) System and the Central/State Corporation System in the ratio of 90 : 10.

15. Minimum Export Price (Floor Prices).—Normally, there shall be only one floor price for each country/category. However, a lower floor price may be fixed for Slow Moving Items. A lower price for children's garments where conversion of adult garments to higher number of children's garments is permitted. The Textile Commissioner will prescribe such prices. In determining them he will take into account all relevant factors including the fact whether a particular item has been identified as Slow Moving or not.

16. Validity Period of Certification of Export Entitlement.—A certification on the shipping bills shall be valid for a period of 30 days except in the case of Open Tender System and First-Come-First-Served Small Order System where the validity period will be restricted upto 60 days.

17. Letter of Credit.—The allocation for all garments and knitwear will be made on basis of credit terms. Letter of Credit should be operative, valid and irrevocable. In the case of all Systems of Entitlement, Letter of Credit should be produced at the time of obtaining certification. Letter of Credit will not be required for slow moving items declared as such in terms of para 12(i). Third party shipments are not allowed.

18. Earnest Money Deposit/Bank Guarantee and Forfeiture thereon.—(i) In the case of PPE, MEE and NOE Systems exporter will not be required to furnish Earnest Money Deposit or Bank Guarantee. However, he must utilise 50 per cent of the allocation on or before 31st May and the remaining 50 per cent by 30th September. The unutilised portion during any period will automatically stand surrendered except as provided in para (ii) below :

(ii) The validity of PPE, MEE and NOE would be restricted to 30th September. However, validity can be extended upto 31st December against specific

contracts backed by Letter of Credit subject to submission of Earnest Money Deposit/Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of FOB value.

(iii) In the case of FCFS (Small Order) System, Open Tender System and Central/State Corporation System, an exporter shall be required to give performance bond backed by Earnest Money Deposit/Bank Guarantee @ 5 per cent of the FOB value on the quantities applied for.

(iv) An exporter who exports less than 100 per cent of the export entitlement in a particular period under Open Tender System, FCFS (Small Order) or Central/State Corporations systems or during the revalidation period as indicated in para (ii) above in case of PPE, MEE and NQE System or transferred PPE will be liable to forfeiture of EMD/BG. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 100 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable to forfeiture of EMD/BG in full.

(v) These provisions will be subject to conditions of force majeure wherever these arise.

(vi) For slow moving items, the Earnest Money Deposit/Bank Guarantee as indicated in paras 12(ii) and (iii) will be applicable.

(vii) In the case of Central/State Corporations where utilisation is not less than 75 per cent within the validity period exporter will have the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for such extension would be filed within one month of the end of the relevant allotment period. In such cases exporter will have to furnish EMD/BG at double the normal rate for balance quantity. In the case of his failure to export fully, the EMD/BG will be liable to be forfeited in full.

(viii) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

19. Appeal against Forfeiture of EMD/BGs.—For the purpose of giving the consideration to representation made by the exporters against forfeiture of EMD/BG for non-utilisation of allotted export entitlement, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD/BG by the AEPC the exporter concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within 15 days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upto receipt of the representation

give a ruling as early as possible. If in any case the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Ministry of Textiles and will be dealt with by the Appellate Committee constituted by the Government.

20. Merger of available Quantities on 30th September.—Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, all balance quantities available as on 30th September from unallocated levels or surrenders from all Systems shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the Tender system for superfast categories and under the FCFS (Small Order) System for the remaining items without any reservation for different segments.

21. Supervision of Allocation of Export Entitlement.—Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day-to-day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and representatives of the concerned EPC as Members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

22. Clearance by Customs.—(A) Products under restraint including items not subject to specific limits in USA.—Shipments will be allowed by Customs Authorities at the ports of shipments after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the AEPC.

(B) Handloom Garments.—In so far as exports of all handloom garments except Tailored Collar shirts corresponding to restrained items in Canada, Cotton handloom garments to Austria, special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories to USA, EEC, Norway, Finland, shipments will be permitted by the Customs on the basis of Inspection Endorsement by the Textile Committee in part 2 of the combination form.

(C) Garments falling under India Items.—In respect of India Items which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Norway and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

23. (A) Export Certificate, Certificate of Origin and Visa.—The following certificates required under the relevant bilateral textile agreements will be issued by AEPC or any other agency duly authorised in this behalf :—

- (i) EEC—(a) Export Certificates and Certificate of origin for all garments|knitwear items under restraint.
- (b) Certificates of Origin for all non-restrained garments|knitwear items.
- (ii) Finland.—Export Certificates for restrained items.
- (iii) Sweden.—Export Certificates for restrained items.
- (iv) Austria.—Export Certificates for garments subject to restraint or surveillance.
- (v) Norway.—Export certificate and certificate of origin in respect of categories subject to specific limits.
- (vi) Canada.—Export Certificate for garments of knitted, powerloom and mill made origin which are subject to restraint export for consignments valued at Canadian \$ 500 or less.
- (vii) USA.—Visa for all garments|knitwear consignments valued over US \$ 250.

(B) Handloom Certificate.—In the case of export of all handloom garments except Tailored Collar shirts corresponding to restrained items to Canada, cotton handloom garments to Austria and special quantities reserved for Handloom Garments in some

of the restrained categories to EEC, Norway and Finland the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the bilateral Agreements for such products.

23. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

24. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. The Apparel Export Promotion Council, Sahyog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi.
2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-1.
3. Office of the Textile Commissioner, Post Box 11500, Bombay-400028.
4. Textile Committee, "Crystal", 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.
5. Development Commissioner (Handicrafts), West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

Sd/-

R. L. MISRA, Chief Controller
of Imports & Exports

H. C. AZAD, Controller
of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports

